

खबर संक्षेप

मोदी जी के 11 वर्ष संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम हेतु बैठक 6 जून को

मण्डला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने बताया मोदी सरकार के 11 वर्ष संकल्प से सिद्धि तक एवं विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस, आपातकाल काला अध्याय कार्यक्रम हेतु दिनांक 06 जून 2025 को समय दोपहर 2 बजे दिन शुक्रवार भाजपा कार्यालय मण्डला में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में वरिष्ठजनों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कार्यशाला (बैठक) में जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, मण्डल अध्यक्ष,महामंत्री, मोर्चों के जिलाध्यक्ष, प्रकोष्ठ के संयोजक, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, कार्यक्रम की जिला टोली एवं मण्डल टोली के संयोजक, सहसंयोजक कार्यशाला में उपस्थित रहेंगे। सभी अपेक्षित कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि समय पर उपस्थित होंवे।

शासकीय आईटीआई में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन 16 तक

मण्डला। प्राचार्य आईटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार समस्त शासकीय आईटीआई में संचालित NCVT/SCVT के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन/ रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार हेतु तिथि दिनांक 16 जून 2025 कर दी गई हैं। इसके साथ ही इस वर्ष महिलाओं के लिए समस्त व्यवसायों में 35 प्रतिषत स्थान आरक्षित हैं। आईटीआई में स्थापित हेल्प डेस्क में रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध हैं। इच्छुक अभ्यार्थी ऑनलाइन के माध्यम से विभाग के डीएसडी पोर्टल www.dsdlmp.gov.in पर प्रवेश रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन/ रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार आदि कर सकेंगे। प्रवेश से संबंधित समस्त जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है अधिक जानकारी के लिए आवेक विभाग के डीएसडी पोर्टल पर अथवा निकट की शासकीय आई0टी0आई0 में स्थापित हेल्प डेस्क से स्वयं उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर सेन समाज के पदाधिकारियों ने ली भाजपा की सदस्यता

हरिभूमि न्यूज ►► मण्डला

मंडला में भाजपा की रीति-नीति से प्रभावित होकर दर्जनों लोगों ने भाजपा जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा के नेतृत्व में भाजपा का दामन थामा। सभी ने भाजपा में अपनी जिम्मेदारी, भूमिका निभाने की शपथ ली। सभी ने कहा कि वे पार्टी के प्रति हमेशा ईमानदार रहेंगे और पार्टी की गरिमा बनाए रखेंगे। जिला अध्यक्ष ने सभी को माला पहनाकर स्वागत किया। जिसमें सेन समाज के अध्यक्ष टीकाराम श्रीवास, चंद्रेश श्रीवास,



ओंकार पटेल, जनार्दन साहू, अतुल राय, सागर पटेल, सम्पत श्रीवास सहित सेन समाज के अनेक पदाधिकारियों ने भाजपा की

सदस्यता ली है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने कहा कि आज आप सभी का विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में स्वागत है।

भाजपा ही देश और छग को कुशल, सक्षम और बेदाग नेतृत्व देकर आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा केंद्र की भाजपा सरकार की स्पष्ट नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य शैली से सभी प्रभावित है। केंद्र की सरकार ने गरीब कल्याण के लिए ऐतिहासिक कार्य किया हैं। इसलिए अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता बढ़ रही है। हर वर्ग का व्यक्ति बीजेपी से जुड़ना चाहता है इसलिए पार्टी ने तय किया है। साथ उन्होंने कहा कि अन्य राजनीतिक

दलों के कार्यकर्ता जो भाजपा की नीति से उत्साहित होकर भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। उनके लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित कर सदस्यता किए जायेंगे। जिसमें उनको सदस्यता दिलाई गई है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा सहित नगर मंडल अध्यक्ष शिवा रानू राजपूत, सालिकराम उसराटे, दीपांशु सेन, जितेंद्र श्रीवास, दीपा श्रीवास, प्रीति श्रीवास, साधना उसराटे , संदीप श्रीवास सहित कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा पीएचई विभाग की समीक्षा बैठक में सीईओ जिला पंचायत के निर्देश।

पूर्व से स्वीकृत योजनाओं का कार्य समय पर पूर्ण करें

* 338 योजनाओं के अपूर्ण रहने पर नाराज दिखे सीईओ।

हरिभूमि न्यूज ►► मण्डला

सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट ने बुधवार को जिला योजना भवन में पीएचई विभाग की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि पूर्व से स्वीकृत सभी योजनाओं का कार्य समय में पूर्ण करें। कम्प्लिट योजना ही संबंधित निकाय को हेडओवर करें। बैठक में फरवरी 2024 तक स्वीकृत हो चुकी योजनाओं में से जिले की 338 योजनाओं के समय पूर्ण नहीं होने पर सीईओ जिला पंचायत ने नाराजगी व्यक्त की। बैठक में जनपदवार विविध कारणों से बंद योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित योजनाओं के लिए समस्याओं चिह्नित किया गया। सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि संबंधित समस्याओं के लिए एसडीएम तथा सीईओ जनपद पंचायत के साथ समन्वय करते हुए



निराकरण कराएं। किसी भी स्थिति जल प्रदाय बाधित नहीं होना चाहिए। जल निगम, एमपीआरडीसी अथवा अन्य एंजेसी द्वारा पाईप लाइन डेमेज करने पर मरम्मत कराने के लिए आवश्यकता पत्राचार करें। उन्होंने वीसी के माध्यम से जुड़े. सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि एक से अधिक कारणों से बंद योजनाओं के लिए अनुविभाग में

पीएचई, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा संबंधित एंजेसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए निराकरण सुनिश्चित कराएं। सीईओ जिला पंचायत श्री कूमट ने कार्यपालन यंत्री पीएचई को निर्देशित किया निर्देशित करते हुए कहा कि विभाग द्वारा खनित असफल नलकूपों की अनिवार्यतः कैपिंग कराएं। कुछ चिन्हित असफल नलकूपों को

रिचार्ज करने के लिए पिट बनाकर नवाचार करें। रिचार्ज सफल होने पर यह प्रयोग अन्य असफल नलकूपों में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी सांकेतिक वृक्षारोपण आवश्यक कराएं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदाय योजनाओं सतत चले यह विभाग को जिम्मेदारी है। किसी योजना विषेष में समस्या आने की स्थिति में

3 दिन के भीतर सीईओ जनपद पंचायत के संज्ञान में लाएं। 5 दिनों में भी निराकरण ना हो तो संबंधित एसडीएम की जानकारी में लाना सुनिश्चित करें। बैठक में कार्यपालन यंत्री पीएचई श्री मनोज भार्स्कर सहित पीएचई के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में वीसी के माध्यम से समस्त एसडीएम तथा सीईओ जिला पंचायत भी शामिल हुए।

जिला शिक्षा केन्द्र के दांव-पेंच में उलझा बुजबुजिया स्कूल

बच्चों को अब भी नहीं मिला सुरक्षित अध्ययन स्थल

* बिना संतुष्टि के बंद करा दी गई सीएम हेल्पलाइन।

हरिभूमि न्यूज ►► मण्डला

अजीब विडम्बना है कि सप्ताह में 02 दिन अनिवार्य रूप से जिले के महत्वपूर्ण विभागों के शीर्ष अधिकारी एक स्थान पर एकत्रित होते हैं शासकीय योजनाओं की समीक्षा करते हैं निर्माण कार्यों पर चर्चा होती है और निर्देशों की एक लम्बी फेहरिस्त जारी होती है बावजूद इसके व्यवस्था में जो खामियां थी वे अभी भी बदस्तूर यथावत हैं। प्रशासनिक अधिकारी नवीन निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं और वर्षों से अधूरे पड़े निर्माण कार्यों की सुध लेना वाला कोई नहीं। तकनीकी अधिकारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुये कार्यक्रमों के आयोजनों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी निर्माण कार्यों की बारीकियां देख रहे हैं अब यदि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता होता है या निर्माण कार्य अपूर्ण रहते हैं तो फिर इसका जिम्मेदार कौन?

जनपद पंचायत मण्डला के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुलाहा के ग्राम बुजबुजिया में वर्षों से शाला भवन निर्माण की बात जोह रहे बच्चों और ग्रामीणों की उम्मीदें एक बार फिर अधूरी रह गई हैं। नवीन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बच्चों के पास अब भी न तो पढ़ने के लिए भवन है और न ही किसी स्थायी स्थान की व्यवस्था। विगत वर्ष की भांति इस बार भी विद्यालय संचालन को लेकर संकट गहराया हुआ है।

पिछले वर्ष जब मीडिया में मामला उजागर हुआ था, कि शाला का संचालन पेड़ के नीचे हो रहा है।



तब विभाग ने आनन-फानन मे किसी ग्रामीण के घर में अस्थायी रूप से विद्यालय संचालन की व्यवस्था की थी, लेकिन इस बार न तो ऐसा कोई प्रबंध किया गया है और न ही कोई वैकल्पिक समाधान सामने आया है।

शिकायत दर्ज, लेकिन समाधान अधूरा

ग्राम में शाला भवन निर्माण को लेकर 21 दिसंबर 2024 को सीएम हेल्पलाइन (शिकायत क्रमांक 30257385) पर शिकायत दर्ज की गई थी। विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि वर्ष 2024-25 की कार्ययोजना में राज्य शिक्षा केंद्र से नवीन भवन की स्वीकृति मांगी गई है, परंतु स्वीकृति न मिलने के चलते कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। इससे भी गंभीर बात यह है कि शिकायतकर्ता की असंतुष्टि के बावजूद शिकायत को बंद कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वे शिकायत को

पुनः खोलने की तैयारी कर रहे हैं।

2012-13 से अधूरा निर्माण, अब तक कोई जवाबदेही नहीं

सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि वर्ष 2012-13 में प्राथमिक शाला बुजबुजिया के लिए अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु 3,01,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें से 1,43,563 रुपये ग्राम पंचायत के खाते में स्थानांतरित की गई थी। बावजूद इसके निर्माण कार्य आज तक अधूरा पड़ा है। विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि इतने वर्षों में न तो कोई निगरानी की गई और न ही कोई वैकल्पिक कार्यवाही की गई।

अब जब मामला सार्वजनिक हो चुका है, तो विभाग ग्राम पंचायत से राशि की वापसी की मांग कर रहा है। सवाल यह है कि समय रहते विभाग ने कार्य न होने पर निर्माण एजेंसी क्यों नहीं बदली? क्या विभाग को यह तक याद नहीं रहा कि उसने

निर्माण के लिए राशि दी थी?

स्थानीय लोगों की मांग और विभागीय असंवेदनशीलता

ग्रामीणों का कहना है कि जो राशि अतिरिक्त कक्ष के लिए दी गई थी, उसी से पुराने भवन की मरम्मत कराकर विद्यालय संचालन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले सत्र में ग्रामीण के घर में अस्थायी रूप से स्कूल चलाया गया था, लेकिन विभाग द्वारा किराया नहीं दिए जाने के कारण पंचायत को वह राशि चुकानी पड़ी। इस बार संबंधित ग्रामीण ने अपने घर में स्कूल लगाने से इनकार कर दिया है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है।

बच्चों को भुगताना पड़ रहा है लापरवाही का खामियाजा

इस सम्पूर्ण विभागीय लापरवाही का सीधा असर गांव के बच्चों पर पड़

जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रहा है।

फिलहाल ग्रामीणों की एकमात्र अपेक्षा है कि शिक्षा का मूल अधिकार सुरक्षित रहे और बच्चों को जल्द से जल्द पढ़ने के लिए एक समुचित स्थान प्रदान किया जाए।

इनका कहना :-

पूर्व सरपंच, सचिव द्वारा यह निर्माण कार्य क्यों नहीं कराया गया जब मेरे को जानकारी मे आया तो मैंने बैंक राशि का पता किया तो राशि बैंक मे सुरक्षित है, अब ब्याज सहित राशि दो लाख से ऊपर की हो गयी, जिसके उपयोग के लिए मैंने जिला शिक्षा केन्द्र को पत्र लिखकर मांग की है कि वर्तमान पंचायत द्वारा निर्माण कार्य अनुमोदन मिलने पर कराया जा सकता है किन्तु विभाग के अधिकारी अनुमोदन नही दे रहे हैं

जिससे अभी भी निर्माण कार्य नहीं कराया जा पा रहा है। और स्कूल सुरक्षित स्थान पर संचालन की समस्या बनी हुई है।

-नरेश मार्को,सरपंच , ग्राम पंचायत सिलपुरा यह बाद सत्य है और मेरी जानकारी मे है किन्तु वरिष्ठ कार्यालय से नये स्कूल भवन की अभी तक स्वीकृति न मिलने के कारण शाला भवन नही बन सका, अगर ग्राम पंचायत के पास जो राशि अतिरिक्त कक्ष की जमा है उसका प्रस्ताव बनाकर भेजे तो पुराने भवन के मरम्मत कार्य का वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमोदन लेकर पंचायत को मरम्मत कार्य के लिए आदेशित कर दिया जायेगा, जिससे वर्तमान स्कूल संचालन की व्यवस्था हो सकती है।

-अरविंद विश्वकर्मा, डीपीसी मण्डला



राकेश कुमार क्रान्त बने संभागीय डाक सेवक संघ के अध्यक्ष

भुआबिछिया। अखिल भारतीय



ग्रामीण डाक सेवक (मंडला-डिंडोरी जिला) संघ डिविजन दोनों जिलों के समस्त डाक सेवको ने सर्व सम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया। रामसिंह धाकड़ परिमंडल सचिव भोपाल,दशरथ प्रसाद गौतम रीजनल सचिव

जबलपुर और आर. पी. गर्ग सोसायटी अध्यक्ष जबलपुर की गरिमामयी उपरित्थि में संभागीय टीम का गठन किया। जिसमें राकेश कुमार क्रान्त अध्यक्ष, सचिव शंकरलाल यादव, कोषाध्यक्ष कमलेश सिंगौर और कार्यकारिणी सदस्यों में चमरू दास पडवार, रमेश मार्को, संतूलाल धुर्वे, रामकुमार धुर्वे, यशवंत चंद्रैल, लीलाधर साहू, मायाप्रकाश डहेरिया, अतुलेंद्र सिंगौर, अमन भोतेकर, सुरेंद्र नेनाम, विशाल जंधेला, विनोद गंगलोद, मनोज ठाकुर, लोकेश चंद्रैल, परमानंद झरिया, नीलेश यादव, हरिंद्र साहू, अशोक भांवरे, सुभद्र बंदेवार, मोनिका मिश्रा शामिल है।

नारायणगंज का बस स्टैंड बना कचरा घर

* पंचायत एवं जनपद के अधिकारी, जनप्रतिनिधि गहरी नींद में।

हरिभूमि न्यूज ►► मण्डला/नारायणगंज

जनपद पंचायत नारायणगंज के मुख्यालय की ग्राम पंचायत पडरिया के द्वारा बरसात के आने के पहले नालियां साफ कराने का कार्य किया जा रहा है नालियों से कचरे को निकाल कर बाहर रख दिया गया है जिसे विगत तीन दिनों से हटया नहीं गया है जिससे आमजनों में खासा गुस्सा नजर आ रहा है और कचरे के प्रदूषण से बीमारियों को भी आमंत्रण दिया जा रहा है।

आखिर कब तक सजा

कर रखा जाएगा मलवा

ग्राम पंचायत पडरिया द्वारा नालियों की सफाई का कार्य किया जा रहा



है परंतु निकले मलवे और कचरे को व्यवस्थित जगह न फेंक कर बीच बस स्टैंड में निकाल कर रख दिया गया है जिससे आमजनों में अच्छा खासा रोस व्याप्त है और अनेको बीमारियों को भी आमंत्रण दिया जा रहा है।

ग्राम पंचायत पडरिया की कार्यशैली पर उठते रहे हैं सवाल



विगत वर्षों में पंचायत पडरिया द्वारा किए गए कार्यों को समय अधि में न करना गुणवत्ता का ध्यान न रखना पंचायत पडरिया की आदत में आ गया है सूत्रों की माने तो इनकी सुस्त कार्यशैली से जनता परेशान नजर आती है। नारायणगंज के बस स्टैंड से जबलपुर जाने वाली सड़क पर बहुत बड़ा गड्ढा है जिसके निर्माण के लिए राशि पंचायत के खाते में भी आ गई है परंतु आज दिनांक तक गड्ढे की मरम्मत का कार्य पंचायत के द्वारा नहीं कराया जा रहा है।

जनपद पंचायत नारायणगंज के उच्च अधिकारियों से जनता का निवेदन है कि कचरे को यथा स्थान में फिकवाया जाए और गड्ढे की मरम्मत का कार्य यथा शीघ्र कराया जाए जिससे आवागम में हो रही परेशानी से निजात मिले।

ख़बर संक्षेप

वन समितियों की देखरेख में तेजी से संग्रहित हो रहा तेंदूपता



हरिभूमि न्यूज़/गाइरवारा। इन दिनों क्षेत्र में वन विभाग द्वारा बनाई गई सालीचौका, चीचली, गोटीटोरिया यूनिट की देखरेख में व्यवस्थित ढंग से जंगल क्षेत्र में तेंदूपता का संग्रहण का कार्य जारी है, जिससे उम्मीद है कि वन समितियों को तेंदूपता के संग्रहण का जो लक्ष्य दिया गया है वह पूर्ण जायेगा। गौरतलब है कि इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी में तेंदूपता संग्रहण कार्य के दौरान वन क्षेत्र के आसपास के गांवों के आदिवासी, मजदूरों को अच्छी आय का साधन साबित हो रहा है, वहीं उनका वक्त खुशी के साथ कट रहा है, वन समितियों से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष गर्मी अधिक पड़ने से पिछले वर्ष की तुलना में क्षेत्र के जंगल के तेंदूपता की गुणवत्ता बेहतर होने से इस कार्य में ज्यादा सहयोग मिल रहा है। आमतौर पर एक मजदूर दिन भर में लगभग 300 गड्डी तेंदूपता को संग्रहण लगभग 500 से लेकर 700 रूपया तक प्राप्त कर लेता है जिसके चलते उसकी मजदूरी निकल आती है। क्षेत्र के वनांचल के गांवों में रहने वाले आदिवासी हर साल बेसरी से तेंदूपता संग्रहण क कार्य शुरू होने का अप्रैल मो से इंतजार करने लगे है। ज्ञात हो कि क्षेत्र के वनांचल में उपजा तेंदूपता हमेशा से अपनी गुणवत्ता को लेकर श्रेष्ठ माना जाता है जिसे खरीदने बाहर के व्यापारी लालायित रहते है।

गांवों में किसानों के कृषि यंत्रों की चोरी पर अंकुश लगाने में पुलिस क्यों नहीं हो रही सफल

हरिभूमि न्यूज़/सड़मुर। इस समय जिस प्रकार से क्षेत्र में चोरी की घटनाएं घटित हो रही है उसके चलते क्षेत्र के लोग लगातार दहशत की स्थिति में तो देखे ही जा रहे हैं।मगर अब स्थिति इस प्रकार से देखने मिल रही है कि किसानों के खेतों पर रखे हुए कृषि यंत्रों की चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी होने के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि इस समय पड़ रही गर्मी के मौसम के चलते किसानों को सिंचाई हेतु मुश्किल से ही बिजली मिल पा रही है जिसके चलते किसान अपने खेतों में लगाई हुई मूक व गन्ने की फसल की सिंचाई चिमचिलाती धूप की परवाह किये बगैर करने में लगा हुआ है।मगर जब देखा जाता है कि किसान अपने खेतों से थोड़ी देर के लिए जब अलग होता है तो वहां पर रखे हुए कृषियंत्रों पर आपो हाथ साफ करने वाले कोई मौका नहीं छोड़ रहे है जिसके चलते क्षेत्र के किसान दहशत में देखे जा रहे है इस प्रकार से किसानों के कृषि यंत्रों की चोरी की घटनाओं के चलते जहां क्षेत्र के किसानों को आर्थिक क्षति का सामना तो करना ही पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर उनके कृषि कार्य में भी काफी व्य्थान पैदा हो रहा है। कुछ इसी प्रकार की सच्चाई क्षेत्र के अनेक गांवों में देखने मिल रही है। वहीं दूसरी ओर बताया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में घटने से बंकर शराब के अवैध कारोबार का परिणाम भी है कि इस प्रकार से चोरी जैसी घटनाएं आम होती जा रही है। क्योंकि इस भीषण मरगई के दे में जब युवाओं को इस प्रकार से नशे की लत लग जाती है और उसे पूरी करने के लिए युवाओं के पास जब धन का अभाव होता है तो वह इस प्रकार से चोरी जैसे कदम उठाते हुए अपनी लत को पूरी करने से नहीं चूकते हैं। इस संबंध में लोगों का कहना है कि यदि गांव गांव बिक रही अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगा जावे तो निश्चित ही इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

बिना नम्बर के चल रहे सैकड़ों टैक्टर से दुर्घटना की बनी आशंका

हरिभूमि न्यूज़/नांदनेर/गाइरवारा

जहां एक ओर प्रशासन द्वारा क्षेत्र के अनेक जगहों पर चैकिंग प्लग लाकर वाहनों की चैकिंग तो की जा रही है, मगर इसके बाद भी जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा ऐसे वाहनों को नजर अंदाज किया जा रहा है जो वर्षों से बगैर नम्बर प्लेट के दौड़ रहे है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो ट्रैक्टर क्षेत्र में रेत, मुरुम का अवैध उत्खनन लगातार हो रहा है, एक तरफ जहां कभी कभी विभाग द्वारा इस ओर कार्रवाई की जा रही है, वहीं अवैध उत्खनन करने वाले अपने उत्खनन के दौरान अधिकांश रेत कोरोबारी उन ट्रैक्टरों को उपयोग में ला रहे है जिनमें नम्बर नहीं लिखा हुआ है, इस प्रकार से बगैर नम्बरों के ट्रैक्टरों से दुलाई कराने को ट्रैक्टर क्षेत्र में रेत, मुरुम राजस्व को लाखों का नुकसान हो रहा है। वहीं इस पर अभी तक आर टी ओ विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने कारण इन ट्रैक्टर वालों के हौसले

शासन द्वारा मूंग खरीदी सहित अन्य मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन



हरिभूमि न्यूज़/गाइरवारा

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आये दिन अपनी मांगों को लेकर लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन के साथ साथ धरना देते हुये अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाता है। मगर बीते हुये दिवस जिस तरह क्षेत्र के अन्नदाता को चीलचिलाती धूप के बीच अर्धग्न अवस्था घुटनों के बल रेकते हुये देखा तो लोगों की आंखों में आंसू छलकने से नहीं चूक पाये वहीं दूसरी ओर आमजन को यह कहते हुये भी सुना की जिन अन्नदाताओं की बल पर आज लोग प्रदेश से लेकर देश की राजधानी में कुर्सी पर बैठे हुये जिम्मेदार एयर कन्डिशन की हवा ले रहे है और सबका पेट भरने वाला किसान आज अपने घुटनों पर रेकते हुये अधिकारियों के समझ अपने खून पसीने को एक करते हुये तैयार की गई फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिये गृहार लगाते हुये देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि बीते हुये कई वर्षों से सरकार द्वारा क्षेत्र के किसानों द्वारा पैदा की जाने वाली गर्मी मौसम की मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता था। मगर इस वर्ष अभी तक न तो मूंग की खरीद शुरू की गई है और न ही उसका पंजीयन करने के लिये कोई दिशा निर्देश जारी किये गये है। जबकि सच्चाई यह है कि क्षेत्र में लगभग अस्सी प्रतिशत किसानों की मूंग कटकर तैयार हो चुकी है। इस तरह मूंग फसल तैयार होने के पुरत बाद उसका विक्रय करने के लिये किसानों को मजबूर इस्लिये होना पड़ता है। क्योंकि मूंग फसल तैयार करते हुये उसमें लगने वाले अनेक प्रकार के रोगों से बचाव को लेकर किसानों को उसमें दबाईयों का छिड़काव किया जाता है उन दबाईयों को किसानों द्वारा दुकानदारों के पास से यह भरोसा दिलाते हुये उधार के रूप में लिया जाता है कि मात्र एक या दो माह बाद मूंग फसल आने के बाद उसे बेचकर उधारी चुका दी जावेगी। इसके आलावा अम्य जरूरी कार्य भी किसान द्वारा मूंग फसल के भरोसे ही किये जाते है। वहीं दूसरी ओर मूंग फसल की कटाई से लेकर उसकी शैथिल सहित अन्य कार्यों में भी पैसा खर्च किया जाता है। इस अपने घर तक मूंग लाने के दौरान किसान काफी हद तक कर्जदार बन चुका होता है। उस कर्ज को

पहले जैसा नहीं रहा क्षेत्र का पर्यावरण, वनों की लगातार कटाई से बिगड़ रहा पृथ्वी का संतुलन

हरिभूमि न्यूज़/ गाइरवारा। भले ही आये दिन हमारे देश से लेकर प्रदेश व क्षेत्र के नेताओं द्वारा पर्यावरण की रक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हुए वृक्षारोपण किया जाता है। मगर इस समय पर्यावरण के साथ खिलबाड़ की जा रही है उसके परिणाम आने वाले भविष्य में भयानक होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. ? क्योंकि मौसम के द्वारा पाठें जब अपना विचित्र खेल दिखाने से क्षेत्रवासियों को चौकाने व चिंतित होने को क्यों मजबूर किया जा रहा है। यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। वहीं दूसरी ओर देखा जावे तो लगातार पर्यावरण के खराब होने का प्रमुख कारण है कि वाहनों की तादात बढ़ने से शहर व गांवो में रोज उठने वाले धुएँ के गुबार किब हद तक माहौल को प्रदूषित कर रहा है और यह बात भी शायद किसी से छिपी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से सड़कों पर वाहन दौड़ते हुए लोगों को धुंआ के रूप में जो जहर परोस रहे है और उससे पर्यावरण पूर्णरूप से खराब हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जिस स्थिति से क्षेत्र में लगातार लग रही नई फैक्ट्री भी प्रदूषण को खराब करने में पीछे नहीं है. ? जिसके चलते स्वच्छ आबो हवा किसी तरह से क्षेत्रवासियों को नहीं मिल पा रही है। इन सबलों को जेहन में कोधने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस आज 5 जून को है। ज्ञातव्य है कि आज गुरुवार को शासन प्रशासन की ओर से जनता को पर्यावरण की रक्षा का संदेश देने के साथ अनेक प्रकार के आयोजन करते हुए लोगों को पर्यावरण की रक्षा करने की जानकारी के लिए शायद कोई आयोजन नहीं रखा गया हो. ? लेकिन आमतौर पर जैसा होता आया है बाद में पर्यावरण को महफूज रखने में सहायक क्षेत्र की नदियों, पहाड़, वृक्षों की हो रही दुर्दशा को भुला दिया गया है। इसके आलावा इस बात पर भी चिंतन करना बंद कर दिया गया है कि आखिर किन कारणों से क्षेत्र का पर्यावरण निरंतर बिगड़ रहा है और इसकी स्थिति में सुधार करने की दिशा में प्रयास करने में हम सार्थक कदम क्यों नहीं उठा पा रहे है। गौरतलब है कि लगभग एक दशक से क्षेत्र के पर्यावरण के खराब होने का सिलसिला शुरू हुआ है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जावे तो जिन सफेद पोश धारियों को आये दिन समाज सेवा की मंत्र पर बडी बडी बाते कूबने के साथ अपने आपको आमजन की नजरों में नालायक बन कर पर्यावरण की रक्षा करने के नाम पर पेड़ लगाते हुये देखा जाता है और उन्हीं के द्वारा अपनी जेबे भरने हरियाली पर कुल्हाड़ी चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है. ? यदि सच्चाई पर गौर किया जावे तो पहले देखा जाता था कि जिस



प्रकार से क्षेत्र के जंगल में खड़े वृक्ष सुकुन भरी हवाओं से झूमते ढटलते थे। मगर अब वे विनागीय अधिकारियों की मनमानी तथा इस जंगल की स्वार्थी जुगाड़ लीला से धराशाही होते चले जा रहे है. ? क्योंकि इन जंगलों की रक्षा



के लिए जिनको जिम्मेदारी सौपी गई थी वही अब वनों को जण्डखाने में अपने अहिम भूमिका निभाते हुए जान पड़ने से नहीं चूक रहे हैं। वहीं दूसरी क्षेत्र के जंगलों में प्लानटेशन की गति धीमी रहने से सदाबाहर वृक्षों की तादाद कम हो गई है। इसी प्रकार से शहर व क्षेत्र के गांवों में पहले चले वृक्षारोपण अभियानों का हथ्र भी बुरा होने से सड़कों में पड़ ही रहा है साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं का रहर है। कुछ इसी प्रकार का हाल क्षेत्र के सरापुड़ा पहाड़ व वृक्षों की बनी हुई है जो लगातार वृक्ष विहीन होते हुए देखा जा रहा है और इसी का परिणाम है कि हर वर्ष पतन में बढ़ोतरी होने से नई चूक रही है जिसकी सच्चाई वर्तमान समय में पड़ रही भीषण गर्मा एक उदाहरण के रूप में मौजूद है। वहीं सरकारों द्वारा भी हर साल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जहां करोड़ों रूपया खर्च करते हुए हरियाली महोत्सव के नाम से योजना चलाते हुए गांव गांव लाखो रूपया बांटते हुए वृक्ष रोपण करया जाता है। मगर शासन की राशि खर्च करते हुए रोपे जाने वाले उन पौधों की क्या सच्चाई है यह शायद ही किसी से छिपी हो. ? जिसको लेकर क्षेत्र की पंचायतों में कागजों के हिसाब से वृक्षारोपण तो हुआ है। मगर सच्चाई यह है कि पंचायतों द्वारा लगाये गये वृक्षों की स्थिति वहां पर बनाये गये द्नी गाई ही बता रहे है कि किस प्रकार से पंचयतों द्वारा वृक्षारोपण किया गया है जो सिर्फ अखबारों की सुर्खियों तक ही दिखाई देते हुए नजर आया है। क्योंकि द्नी गाई में



रो गये वृक्षों की जगह मात्र बेसम के पेड ही दिखाई दे रहे है। जिससे यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि पंचायतों में वृक्षारोपण के नाम पर खर्च की गई राशि



मात्र कागजों व द्नी गाडों तक ही सीमित रही होगी तो दूसरी ओर पर्यावरण को बेहतर बनाने वाली नदियों भी अपना दम तोड़ रही है। वहीं बारह माह अनौषध हवासे चलने के कारण वातावरण विकृत होने से सावन माह में गर्मी और फागुन में ठंडक, ठंड के मौसम में तपिश का अहसास होने से अब यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि कब कौन सा मौसम बेईमान हो जाएगा! विदित हो कि क्षेत्र में पर्यावरण के विगड़ने से जहां जिन स्वस्थ तो खरते में पड़ ही रहा है साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं से क्षेत्रीय किसानों द्वारा से अपने खेतों में बोई जाने वाली फसलों की पैदावार में भी अंतर आ रहा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता है कि शहर में सीमेन्ट, कांक्रीट के जंगलों का विस्तार होने से आमजन जहां वाकित्ता की समस्या से जूझ रहे है। वहीं क्षेत्र में लगातार फैक्ट्रियों का जाल बिछने के कारण उनकी चिमिनियों से उठने वाले धुएँ से भी पर्यावरण की रक्षा नहीं हो पा रही है। क्षेत्र के पर्यावरण की दशा सोचनीय होने से वन्य प्राणी जंगल से पलायन कर शहर और गांवों की ओर भाग रहे है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण की दशा में सुधार करने की दृष्टि से जंगल, सार्वजनिक स्थानों में लगे वृक्षों को बचाने, बेतरतीक बसाहट की रोकथाम के लिए जिम्मेदारों द्वारा शायद ही निष्ठा पूर्वक कमी भी प्रयास नहीं किए गये है और इसी का नतीजा है कि पर्यावरण बिगड़ने का नतीजा उसे क्षेत्र की नई पीढ़ी को भोगने विवश होना पड़ रहा है?

अन्नदाता किसानों ने मूंग फसल की खरीदी को लेकर किया अनोखा प्रदर्शन



अर्धग्न अवस्था में घुटनों के बल गृहार लगाने रेगते हुये पहुंचे एसडीएम कार्यालय



प्लोटनगंज देवी मंदिर के पास एकर होकर मूंग फसल को शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग करते हुये विरोध प्रर्श्रजन करते हुये रैली निकाली गई। इसके बाद आक्रोशित किसान अर्धग्न अवस्था में होकर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय घुटनों के बल रेगते हुये गृहार लगाने के लिये पहुंचे। इस प्रकार से नगर में पहलीबार देखने मला है कि जब क्षेत्र का अन्नदाता अपने घुटने के बल आते हुये अपने आपको को किसानों की सरकार कहने वाली सरकार के राज्य में इस तरह किसानों की स्थिति दिखाई देना निश्चित तौर से चिंता जनक संदेश देने से नहीं चूक पा रही है. ? इस प्रकार से मूंग फसल की समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग करने के लिये घुटनों पर रेगते हुये अन्नदाता की सच्चाई को देखकर जहां लोगों की आंखों में आंसू छलकते हुये दिखाई देने से नहीं चूक रहे थे. ? वहीं दूसरी ओर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर किसानों द्वारा मूंग फसल की समर्थन मूल्य पर खरीदी सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्य मंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी कलावति व्गारे को ज्ञापन सौंपा गया। सौपे गये ज्ञापन में उल्लेखित किया गया है कि गाइरवारा सहित संपूर्ण जिले का किसान गर्मी मूंग फसल को काफी मात्रा में पैदा करते है और यही उनके मरण पोषण का मुख्य स्रोत है। सरकार द्वारा बीते हुये कई वर्षों से किसानों द्वारा पैदा की जाने वाली गर्मी मौसम की मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीद करते हुये किसानों को लाम देती थी। मगर इस वर्ष किसानों की मूंग खरीदने की बात तो दूर उसका पंजीयन करने के लिये भी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये है। जबकि क्षेत्र के लगभग अस्सी प्रतिशत किसानों की मूंग फसल तैयार हो चुकी है और उसे व्यापारियों के पास आने पोने दामों में बेचने के लिये मजबूर हो रहा है। हम मांग करते हुये हम किसानों की मूंग फसल का शोषता के साथ समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू की जावे। वहीं दूसरी ओर समीपस्थ गाम कोडिया स्थित

शक्ति शुगर मिल द्वारा किसानों का प्रति क्विंटल 20 रूपया की राशि जो रोककर रखी गई उसका शीघ्र मुगतान करया जावे। वहीं दूसरी ओर राजस्व विभाग में भीषण अनियमितताये का जो बोल बाला है उस पर अंकुश लगाया जावे। वहीं दूसरी ओर किसानों के मोटर पंपों सहित घरेलू बिजली बिल मनमाने तौर से बढ़ाते हुये भेजे जा रहे है जंमें सुधार करया जावे। वहीं दूसरी ओर अनाज मंडी में किसानों जिस तरह व्यापारियों द्वारा प्रति क्विंटल पर 700 गाम अधिक तुलाई की जा रही है उसको बंद करया जावे। इसके आलावा किसानों की फसलो को जंगली जानवरों द्वारा क्षति पहुंचाई जा रही है उस पर मुआवजा प्रदान करने के साथ साथ फनटीपीसी से निकलने वाले राख का परिवहन करने वाले भारी भरकम डमफरों की धमाचौकड़ी पर रोक लगाई जावे। क्योंकि क्षेत्र की सड़के इस क्षमता व चौड़ाई की नहीं बनी हुई है जो इस समय दौड़ रहे ट्राला रूपी डमफरों की मार सह सके। इन डमफरों से आये दिन सड़क दुर्घटनाओं के चलते लोग बेमती मरते हुये देखे जा रहे है। इस तरह आक्रोशित किसानों द्वारा अपनी मांगों से परिपूर्ण ज्ञापन अनोखा प्रदर्शन करते हुये अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान गाइरवारा तहसील क्षेत्र के आलावा साईंखेड़ा व चीचली कोडिया क्षेत्र से आये हुये सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद थे। इस प्रकार से अन्नदाताओं के आक्रोश को देखते हुये धरना स्थल से लेकर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय तक काफी पुलिस बल तैनात रहने के चलते प्लोटन गंज पुलिस ठाकनी के रूप में नजर आने से नहीं चूक रहा था। इस तरह जहां क्षेत्र का किसान अपने घुटनों पर रेगते हुये अपनी फसल का मूल्य मांगते हुये देखा जा रहा है तो दूसरी ओर नगर में प्रदेश के मुख्यमंत्री के आने की तैयारियों चलते हुये देखी जा रही है। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि यह क्षेत्र का अन्नदाता किसान प्रदेश के मुखिया के समझ भी इस प्रकार से गृहार लगाने के लिये पहुंचेगा. ?

निजी कंपनी के मोबाईल टावर को लेकर मनमानी

ग्रामीणों की जिन्दगी को दांव पर लगाते हुये मार्ग के समीप स्थापित की जा रही डीपी

हरिभूमि न्यूज़/सालीचौका। क्षेत्र के स्थापित हो रही निजी कंपनी द्वारा जिस तरह अपने स्वा्थ का ध्यान रखते हुये काम किये जाते है उस दौरान व आम लोगों की ज़िन्दगी की सुरक्षा से लेकर परेशानी को नजर अंदाज इस तरह से किया जाता है कि बाद में लोगों को अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। इतना ही नहीं इन निजी कर्पनियों की मनमानी को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा चुपों साथी जाती है उसके चलते जहां इनके हौसले बुलंद होने से नहीं चूकते है तो दूसरी ओर बाद में पछताने के लिये मजबूर होना पड़ता है..? कुछ इसी प्रकार की सच्चाई इस समय समीपस्थ ग्राम सहावन में देखने मिल रही है। बताया जाता है कि ग्राम सहावन में एक निजी मोबाईल कंपनी द्वारा स्थापित किये गये अपने टावर तक बिजली पहुंचाने के लिये जिस प्रकार से लाइन खड़ी कराई जा रहे है उसके चलते जहां गांव के मुख्य मार्ग के पास खम्बे लगाये जाने के चलते यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने से नहीं चूकेगा। वहीं दूसरी ओर मार्ग किनारे ही लगाये जाने वाला ट्रांसफार्मर के चलते ग्रामवासियों की जिन्दगी को खतरा पैदा होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है..? बताया जाता है कि यह मार्ग गांव के लोगों का मुख्य मार्ग होने के कारण आना जाना बना रहता है तो दूसरी ओर ग्रामीण लोग अपने खेतों से ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से फसल लेकर भी इसी मार्ग से निकलते है। इस स्थिति में मुख्य मार्ग के किनारे इस तरह विद्युत डीपी स्थापित किये जाने के चलते जहां आम लोगों की जिन्दगी को खतरा पैदा होने की संभावना के साथ साथ ग्रामीणों को



अपनी फसल लाने ले जाने में भी परेशानी का सामना करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है..? मगर हैरत की बात है कि इस तरह एक निजी मोबाईल टावर स्थापित करने वाली कंपनी द्वारा की जा रही मनमानी को लेकर जहां बिजली विभाग से लेकर ग्राम स्तर से लेकर उच्च स्तर के जनप्रतिनिधियों द्वारा जिस प्रकार से चुपों साथी जा रही है उसी का परिणाम है कि एक बाहर से आई हुई कंपनी अपनी मनमानी पर उतारू होते हुये देखी जा रही है.. ? इस तरह की जा रही मनमानी को लेकर यदि कोई ग्रामवासी सबाल जबाब करता है तो कंपनी से जुडे हुये लोग उसको अपनी पहुंच की दम द्खाने में भी पीछे नहीं रहते है.. ? इस सच्चाई को देखते हुये यह जान पड़ने से नहीं चूक रहा है कि मानों क्षेत्र के पेहरदार इन बाहरी कंपनियों के गुलाम बन चुके है और ग्राम से लेकर क्षेत्र का अब भगवान ही मालिक है.. ?

दुकानों से लेकर वाहनों में भी धड़ल्ले से हो रहा घरेलू गैस का उपयोग, प्रशासन की भूमिका बनी संदिग्ध?

हरिभूमि न्यूज़/साईंखेड़ा। जहां एक ओर लोगों को इस समय गैस प्राप्त करने के लिए परेशान होते हुए देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग प्रतिबंधित है। मगर इसके बाद भी देखा जा रहा है कि नगर में जहां खुलेआम घरेलू गैस को नियम विरुद्ध तरीके से दुकानों पर व्यवसायिक रूप से उपयोग हो रहा है, इस बात की सच्चाई सड़को पर आलू बंडा, चाट, मुंगोड़ी और अंडे का ठेला लगाने वाले बेहतर जानते है? जब भी किसी अधिकारी को कानून का पालन कराने की याद आती है तो सड़क किनारे से 4-5 सिलेंडर जप्त कर लिये जाते है, परंतु रसूखदार मालिको के बड़े प्रतिष्ठानो पर कार्यवाही करने में अधिकारियो के हाथ में न जाने क्या वही जन जाता है? घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकना खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी है मगर विभाग द्वारा दिखाई जाने वाली सुस्ती से घरेलू उपभोक्ताओं के हक पर डाका डाल रहे होटल संचालको व अन्य व्यवसायियो के हौसले बुलंद है। शान्दियो सीजन के दिभान जहां खुलेआम घरेलू गैस का दुरुपयोग होते हुये देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी जन शम ढले किसी समारोह में सह परिवार पहुंचते है तो वहां हर स्टॉल पर घरेलू सिलेंडरो पर रखे कड़ाहो से दिभून व्यंजन तलकर निकलते है तो वे इनका आनंद लेते हुई दिखाई देने से नहीं चूकते है? इस प्रकार से घरेलू सिलेंडरो का मुद्दा केंटरस के पाले में आते ही उनके रसूख और शान्दियो के ढोल ढमाको में दबकर रह जाता है। वहीं देखा जावे तो प्लेट्सर के आधार ट्रैक्टर का उपयोग करते समय सामने का एक ही लाईट चालू किया जाता है जिससे सामने आने वाला व्यक्ति उसे दो पाहिया वाहन समझकर साईड देता है और वह दुष्टाना प्रस्त हो जाता है।

अतः शासन प्रशासन से मांग की जाती है कि बगैर नम्बर तथा एक लाईट व बगैर लाईट के ट्रैक्टरों के खिलाफ एक मुहित के तहत कार्यवाही की जावें।





डिंडोरी । पावन नर्मदा नदी को निर्मल और अविरल बनाए रखने हेतु नर्मदा पथ सर्वेक्षण एवं

दक्षिण तट से शुरू होकर एमपुरी घाट पर सम्पन्न हुई यात्रा, ग्रामों में चला चौपाल व संवाद कार्यक्रम

यह यात्रा का आ यो ज न जन अभियान परिषद द्वारा किया गया। यात्रा का शुभारंभ 25 मई को किया गया थाए जो 5 जून तक चलेगी। उत्तर तट की यात्रा पूर्ण कर अब दक्षिण तट पर जारी है। इस क्रम में 3 जून को यात्रा विकासखंड डिंडोरी के ग्राम सुबखार रैयत से प्रारंभ हुई। जिला समन्वयक धर्मेन्द्र चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा के दौरान नदी तट की सफाईए घाटों का सर्वेक्षणए तथा ग्रामीणों के बीच स्वच्छताए जैविक खेतीए पौधरोपण एवं जल.गंगा संवर्धन विषयों पर संवाद किया गया। यात्रा सुबखार रैयत से होते हुए औरई रयपुरा और इमलाई माल तक निकली गई। यात्रा का समापन विकासखंड अमरपुर के ग्राम रमपुरी में किया गयाए जहाँ कलश यात्राए जल संरक्षण की शपथ एवं चौपाल का आयोजन किया गया। इस अभियान में नवांकुर संस्थाए नर्मदा सेवा समितिए ग्राम विकास प्रस्फुटन समितिए सीएमसीएलडीपी के छात्र और परामर्शदाता सहित अनेक सामाजिक संगठनों की सक्रिय सहभागिता रही। विकासखंड समन्वयक गणेश राजपूत व अमरलाल धुवें ने भी ग्रामीणों सेसंवाद कर उन्हें पर्यावरण सुरक्षा व नदी संरक्षण के लिए प्रेरित किया। यह यात्रा केवल एक अभियान नहींए बल्कि नर्मदा के प्रति जनजागरण और चेतना का संदेश हैए जो समाज को जल और पर्यावरण संरक्षण की ओर अग्रसर कर रही है।

संत शिरोमणि कबीर नवोदय यात्रा का डिंडोरी में भव्य शुभारंभ पंथ गुरु उदित मुनिनाम साहेब ने दिए आध्यात्मिक संदेश

डिंडोरी । संत शिरोमणि कबीर साहेब की शिक्षाओं और मूल्यों को जन.जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही नव जय सतगुरु कबीर नवोदय यात्रा नव जय का भव्य शुभारंभ 3 जून को डिंडोरी जिले के ऐतिहासिक कबीर चबूतरा से किया गया। इस पावन यात्रा का नेतृत्व पंथ श्री हुजूर उदित मुनिनाम साहेब के सानिध्य में किया जा रहा हैए जो राजस्थान से आरंभ होकर महापट्ट गुजरात होते हुए अब मध्यप्रदेश के डिंडोरी पहुंची है। इस यात्रा का आयोजन केडीवी कबीर दया वंशावली मिशन के तहत किया जा रहा है जिसका उद्देश्य है नवजयजीव दयाए आत्म पूजा और संत कबीर के बताए मार्ग पर चलकर समाज को जागरूक करना। नवजय कबीर चबूतरा से कबीर आश्रम तक निकली भव्य शोभायात्रा जिले के कबीर चबूतरा से आरंभ होकर यह नवोदय यात्रा विभिन्न तहसीलों से होती हुई माँ नर्मदा तट स्थित कबीर आश्रम पहुंची जहाँ जिले भर से आए कबीरपंथियों



तारा वनवासी की ऐतिहासिक सफलता, आदिवासी अंचल की बेटी बनीं सहायक प्राध्यापक, संघर्ष की मिसाल बनीं

डिंडोरी की बनीं प्रेरणा की प्रतीक, सीमित संसाधनों के बावजूद एमपीपीएससी परीक्षा में रचा कीर्तिमान

डिंडोरी । जिले के आदिवासी अंचल से निकली तारा बनवासी ने वह कर दिखाया है जो कई युवाओं के लिए केवल एक सपना होता है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की सहायक प्राध्यापक हिन्दी परीक्षा 2022 में चयनित होकर तारा ने न सिर्फ अपने परिवार और गांव काए बल्कि पूरे आदिवासी समाज और जिले का नाम रोशन किया है।

पढ़ाई के दौरान आर्थिक संकट आड़े आएए लेकिन उन्होंने आत्मनिर्भरता और जुझारूपन से अपनी पढ़ाई जारी रखी। हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर करने के बादए तीसरे प्रयास में छम्प परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर एमपीपीएससी की परीक्षा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।वर्तमान में तारा बनवासी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालयए रीवा से हिन्दी विषय में पीएचडी कर रही हैं। उनकी यह उपलब्धि सिर्फ एक



व्यक्तिगत सफलता नहींए बल्कि यह सामाजिक बदलाव और प्रेरणा की एक नई कहानी है जो विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी बेटियों के लिए एक प्रकाशस्तंभ की तरह है। उनकी इस सफलता पर परिजनए शिक्षकगण ग्रामीणजन और जिले भर के लोग गर्व अनुभव कर रहे हैं। चारों ओर से उन्हें बधाइयाँ मिल रही हैं और वे अब नयी पीढ़ी के लिए एक आदर्श बनकर उभरी हैं। तारा कहती हैंए जब लक्ष्य स्पष्ट हो और मन में विश्वास होए तो कोई भी विपरीत परिस्थिति आपको राह नहीं रोक सकती। आज तारा बनवासी इस सच्चाई की मिसाल हैं कि प्रतिभा को अगर अवसर मिले तो वह किसी भी ऊंचाई को छू सकती है।

प्रतिबंध के बावजूद डिंडोरी में अवैध शराब का धंधा जारी, कार्यवाही सिर्फ औपचारिकता

डिंडोरी । आस्था और श्रद्धा की केंद्र पवित्र नर्मदा नदी के तटों पर स्थित कस्बा और नगरों को पवित्र धार्मिक स्थल घोषित करते हुए पूर्णतः शराब बंदी की घोषणा मध्यप्रदेश में काबिज भाजपा सरकार ने किया था लेकिन सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए जिम्मेदारों के शह शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जिले में नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर के परिधि में शराब की बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूदए अवैध शराब का कारोबार खुलेआम फल.फूल रहा है। प्रशासनिक सख्ती और कानून के प्रावधानों के बावजूद यह गोरखधंधा जिले के कई ग्रामीण व शहरी इलाकों में बेरोकटोक जारी है। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि अवैध शराब के धंधे पर रोक लगाने के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति की जा रही हैए जबकि असली कारोबारी बेखौफ अपने काम में लगे हैं।

नर्मदा किनारे का इलाका बना हॉटस्पॉट

नर्मदा नदी के संरक्षण और आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए 5 किलोमीटर के भीतर शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हैए लेकिन डिंडोरी जिला मुख्यालय में ही कम से कम 20 ठिकानों से दिन दहाड़े लाखों रुपए की अवैध शराब विक्रय किया जा रहा हैए बस स्टैंड से लेकर किराना दुकान और पान दुकानों सहित होम डिलीवरी की सुविधा के साथ अवैध शराब तस्करी जारी है। जिले में शराब बंदी की कानून सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आता है। जिले के कई क्षेत्रों विशेष रूप से करंजियाए बजायाए डिंडोरी और शाहपुर के नर्मदा किनारे के गांवों में कच्ची और देशी शराब का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कई स्थानों पर स्थायी अड्डे बना दिए गए हैं जहाँ शराब बनाई और बेची



जाती है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस और आबकारी विभाग को इन गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही।

आबकारी विभाग की भूमिका पर उठे सवाल

आबकारी विभाग द्वारा समय.समय पर की जाने वाली छापामार कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति तक सीमित नजर आती है। जब भी मीडिया या

उच्चाधिकारियों की नजर जाती हैए विभाग नाम मात्र की कार्रवाई कर छोटी मछलियों को पकड़कर रिपोर्ट बना देता हैए जबकि बड़े सप्लायर और माफिया अब तक कानून की पकड़ से बाहर हैं।

महिलाएं और युवा हो रहे प्रभावित

अवैध शराब के बढ़ते प्रभाव का सीधा असर गांवों में महिलाओं और युवाओं पर दिखाई दे रहा है। कई स्थानों से नशे की लतए घरेलू हिंसाए और बेरोजगारी की समस्याएं सामने आई हैं। समाजसेवियों और महिला संगठनों ने कई बार जिला प्रशासन से शिकायतें की हैंए लेकिन स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए।

जनप्रतिनिधियों की चुप्पी से भी सवाल खड़े

चौकाने वालों बात यह है कि जिले के कई

जनप्रतिनिधि इस गंभीर मुद्दे पर मौन साधे हुए हैं। न तो इस विषय पर कोई खुलकर आवाज उठा रहा है और न ही विधानसभा या जिला स्तर पर इसे प्राथमिकता मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते यह अवैध कारोबार वर्षों से फलता. फूलता आ रहा है।

आवश्यक है ठोस रणनीति और जन सहभागिता

स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि नर्मदा तट क्षेत्र में अवैध शराब पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएए जिसमें पुलिसए आबकारीए ग्राम पंचायत और स्वयंसेवी संस्थाओं की संयुक्त भागीदारी सुनिश्चित हो। साथ ही शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी सजा और संपत्ति जब्त की कार्रवाई हो।



ग्राम पंचायत इंदौरी में मजदूरों के साथ अमद्रता जनपद अध्यक्ष से शिकायत

शहपुरा । शहपुरा जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत इंदौरी में जल गंगा संवर्धन योजना के तहत तलाब निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने सरपंच और सचिव पर तानाशाही रवैये और अभद्रता का आरोप लगाया है।

मामले का विवरण

मजदूरों ने बताया कि मेट द्वारा सरपंच और सचिव के निर्देश पर कार्य बंद करा दिया गया और उनके साथ अभद्रता की गई। इसके विरोध में मजदूरों ने ग्राम पंचायत भवन में दो घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया और सरपंच और सचिव को फोन कर बुलायाए लेकिन वे नहीं पहुंचे।

जनपद अध्यक्ष से शिकायत

मजदूरों ने जनपद अध्यक्ष प्रियंका आर्मा से शिकायत की और सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई की

मांग की। मजदूरों ने आरोप लगाया कि सरपंच और सचिव द्वारा स्टीमेंट से हटकर नियम विरुद्ध कार्य कराया जा रहा है।

मजदूरों की मांग

मजदूरों ने सरपंच और सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और नियमित कार्य कराने की मांग की है।

जनपद अध्यक्ष की प्रतिक्रिया

जनपद अध्यक्ष प्रियंका आर्मा ने मामले की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ग्राम पंचायत इंदौरी में मजदूरों के साथ अभद्रता का मामला गंभीर है और इसकी जांच कर कार्रवाई करना आवश्यक है। हमें उम्मीद है कि जनपद अध्यक्ष की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मजदूरों की अजीबका का शोषण रोका जाएगा।

नगर परिषद के टेंडर में भारी अनियमितता का आरोपए कलेक्टर से जांच की मांग

डिंडोरी । नगर परिषद डिंडोरी द्वारा प्लेट्स प्रिटिंग कार्य हेतु निकाले गए टेंडर में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। इस संबंध में प्रोप रोहित कांस्कर ने विगत दिनांक 3 जून 2025 को कलेक्टरडिंडोरी को एक लिखित आवेदन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है।प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर परिषद द्वारा हाल ही में प्लैक्स प्रिटिंग कार्य के लिए टेंडर आमंत्रित किया गया थाए जिसमें बिरासनी ट्रेडर्स द्वारा कुछ वस्तुओं की दरें बाजार मूल्य से बेहद कम प्रस्तुत की गईं।

आवेदनकर्ता ने बताया कि बिरासनी ट्रेडर्स ने टी.शर्ट प्रिटिंगए केप प्रिटिंग तथा झंडा प्रिटिंग जैसी सामग्री की दर मात्र 09100 पैसे प्रति यूनिट दर्ज की हैए जोकि व्यावहारिकता और बाजार दर के पूर्णतः विपरीत है। इतनी कम दर डालने के बावजूद बिना



वस्तुतः गुणवत्ता या संभाव्यता की जांच किएए केवल एल.1 सबसे न्यूनतम दरदाता होने के आधार पर उक्त संस्था को टेंडर आवंटित कर दिया गया। प्रार्थी ने इसे नियमों का खुला उल्लंघन बताते हुए आपत्ति जताई है।प्रोप रोहित कांस्कर ने अपने आवेदन में कहा है कि यह संदेहास्पद प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता के खिलाफ हैए बल्कि इससे शासन के राजस्व को भी नुकसान हो सकता है। उन्होंने मांग की है कि टेंडर की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। प्रो कांस्कर ने इस संदर्भ में नगर परिषद के संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार की अनियमितताएं बिना जांच के स्वीकृत होती रहें तो आने वाले समय में जनहित के कार्यों में भारी गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं।

